

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

16 जनवरी 2008

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 16 जनवरी 2007

विषय: जीर्ण-शीर्ण राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5(ख)/30532/जीर्ण-शीर्ण/2007-08 दिनांक 10 सितम्बर, 2007 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न 04 (चार) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-3 पर उल्लिखित कार्यदायी निर्माण संस्थाओं द्वारा गठित आगणों के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा स्तम्भ-4 पर अनुमोदित कुल लागत रु0 296.55 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रु0 115.55 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रशस्त योजना में शासनादेश संख्या 1010/XXIV-3/2007/02(20)07 दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा आपके निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि रु0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण संस्था का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	रा0वालिका इ0का0दीलिया, हल्द्वानी, नैनीताल	ग्रा0अभि0सेवा, नैनीताल	66.20	26.20
2	रा0इ0का0 खटीमा, उधमसिंहनगर	ग्रा0अभि0सेवा उधमसिंहनगर	47.60	18.60
3	रा0इ0का0 चौरिया, रुद्रप्रयाग	उ0प्र.रा0 नि0नि0 श्रीनगर,	86.35	34.35
5	रा0इ0का0 गणेशनगर, रुद्रप्रयाग	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर,	96.40	36.40
		योग	296.55	115.55

हस्ताक्षर

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य-नजर एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से अवश्य कर लें। निरीक्षण के उपरान्त स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9) जीपीओडब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(11) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2 यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखी जायेगी।

10. गुणवत्ता/प्रगति की अनुश्रवण हेतु (Third Party Cheeeking) की व्यवस्था प्राथमिकता पर बनायी जाय। इस पर होने वाला व्यय सेट्टेज चार्ज से ही किया जायेगा। अनुश्रवण की एक प्रति प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।



12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा -आयोजनागत-00-11- राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण -24 -बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 600 (पी0)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2007 दिनांक 31.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)

सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्ता, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक, मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग,उधमसिंहनगर,नैनीताल।
- 8- कौषाधिकारी,रूद्रप्रयाग,उधमसिंहनगर,नैनीताल।
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग,उधमसिंहनगर,नैनीताल।
- 10- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 12- संबंधित निर्माण एजेंन्सी।
- 13- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
- 14- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से
(५९)
(पी0एल0शाह)
उप सचिव
2